शनिवार, 18 जुलाई, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

महान ऑलराउंडर सर गारफील्ड सोबर्स का निधन

Page-04

# भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

तीसरी शादी पीआर द्रोलिंग, आमिर ने तोड़ी चुप्पी

Page-05

## भारतीय नौसेना को मिला MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर

भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग लगातार मजबूत होता जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय नौसेना को अत्याधुनिक MH-60R सीहॉक मल्टी-रोल नेवल हेलीकॉप्टर की एक और खेप सौंप दी गई है। अमेरिकी दूतावास ने जानकारी दी कि पिछले सप्ताह कोच्चि में भारतीय नौसेना को नया हेलीकॉप्टर सौंपा गया और आने वाले दिनों में दो अन्य हेलीकॉप्टर भी भारत पहुंचने वाले हैं।अमेरिका में भारत के लिए नियुक्त राजदूत सर्जियो गोर ने इस उपलब्धि को दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी का महत्वपूर्ण उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि MH-60R सीहॉक जैसे अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर हिंद महासागर और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। यह प्लेटफॉर्म पनडुब्बी रोधी युद्ध, समुद्री निगरानी, खोज एवं बचाव अभियान और सतही युद्ध अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।भारतीय नौसेना पहले से ही इन हेलीकॉप्टरों का उपयोग अपने युद्धपोतों के साथ कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इनके शामिल होने से नौसेना की परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती सामरिक गतिविधियों के बीच यह हेलीकॉप्टर समुद्री निगरानी और सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।भारत और अमेरिका के बीच हाल के वर्षों में रक्षा सहयोग तेजी से बढ़ा है। दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा तकनीक, खुफिया साझेदारी और अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों की खरीद के क्षेत्र में लगातार सहयोग बढ़ा रहे हैं। सीहॉक हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति भी इसी व्यापक रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा मानी जा रही है।

## भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन

# हरित रेलवे की दिशा में ऐतिहासिक कदम

भारत ने स्वच्छ ऊर्जा और आधुनिक रेल परिवहन के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल करते हुए अपनी पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित यात्री ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से इस अत्याधुनिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है, जहां हाइड्रोजन तकनीक पर आधारित रेल सेवाएं संचालित हो रही हैं। भारतीय रेलवे ने इस परियोजना को देश के हरित परिवहन मिशन की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है।यह ट्रेन पूरी तरह भारत में डिजाइन और विकसित की गई है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह दुनिया की सबसे लंबी और सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन-पावर्ड पैसेंजर ट्रेनों में शामिल है। इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक का उपयोग किया गया है, जिसके जरिए हाइड्रोजन से बिजली पैदा होती है और उसी ऊर्जा से ट्रेन संचालित होती है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य प्रदूषक गैसों का उत्सर्जन नहीं होता, बल्कि केवल जलवाष्प निकलती है। यही वजह है कि इसे पर्यावरण के अनुकूल परिवहन का भविष्य माना जा रहा है।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल आधुनिक बुनियादी ढांचा ही नहीं बना रहा, बल्कि दुनिया को स्वच्छ और टिकाऊ तकनीक अपनाने का संदेश भी दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रही है और आने वाले वर्षों में देश के कई अन्य मार्गों पर भी हाइड्रोजन ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा।रेल मंत्रालय का कहना है कि इस परियोजना से डीजल पर निर्भरता कम होगी, ईंधन आयात का खर्च घटेगा और कार्बन उत्सर्जन कम करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को भी मजबूती मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल भारत के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति देगी। साथ ही हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण और संबंधित उद्योगों में निवेश तथा रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। भारतीय रेलवे की यह उपलब्धि देश के परिवहन इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है।

## जांच में नया मोड़,SIT 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी अंतरिम रिपोर्ट

अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है। मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) ने उत्तर प्रदेश सरकार से अतिरिक्त समय मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में 20 जुलाई को अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तैयारी पूरी कर ली है। इस रिपोर्ट में अब तक की जांच, दस्तावेजों की समीक्षा और प्रारंभिक निष्कर्ष शामिल किए जाने की संभावना है।सूत्रों के अनुसार जांच टीम ने मंदिर ट्रस्ट से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड, दान संग्रह प्रणाली, बैंक लेनदेन और लेखा-जोखा से संबंधित दस्तावेजों की विस्तृत जांच की है। इसके अलावा कई अधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप एसआईटी अपनी प्रगति रिपोर्ट सीधे अदालत के समक्ष पेश करेगी।मामला उस समय चर्चा में आया था जब मंदिर को प्राप्त दान के प्रबंधन और वित्तीय प्रक्रिया को लेकर अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद जांच के आदेश दिए गए और एसआईटी का गठन किया गया। हालांकि ट्रस्ट की ओर से लगातार कहा गया है कि दान की पूरी व्यवस्था पारदर्शी है और सभी वित्तीय लेनदेन निर्धारित नियमों के तहत किए गए हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट आगे की जांच की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यदि रिपोर्ट में किसी प्रकार की अनियमितता के संकेत मिलते हैं, तो जांच का दायरा और बढ़ाया जा सकता है।

## मानसून सत्र से पहले एनडीए की रणनीति तैयार

# राजनाथ सिंह के आवास पर अमित शाह समेत शीर्ष नेताओं की बैठक

संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने अपनी संसदीय रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सरकारी आवास पर एनडीए के वरिष्ठ नेताओं और फ्लोर लीडर्स की उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई वरिष्ठ मंत्री और गठबंधन के प्रमुख नेता शामिल हुए। इस बैठक का उद्देश्य 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलने वाले संसद के मानसून सत्र के दौरान सरकार की रणनीति और विधायी एजेंडे को अंतिम रूप देना था।बैठक में सरकार के सामने आने वाले प्रमुख विधेयकों, विपक्ष की संभावित रणनीति और सदन के सुचारू संचालन पर विस्तार से चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार सरकार इस सत्र में दो महत्वपूर्ण विधेयकों को प्राथमिकता दे सकती है। इनमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026 तथा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 प्रमुख हैं। सरकार चाहती है कि इन दोनों विधेयकों पर संसद में व्यापक चर्चा के बाद उन्हें पारित कराया जाए।बैठक के दौरान मंत्रियों को विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के सवालों का प्रभावी जवाब देने और सदन में समन्वय बनाकर चलने के निर्देश भी दिए गए। माना जा रहा है कि विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था, विदेश नीति और अन्य समसामयिक विषयों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। ऐसे में एनडीए ने पहले से ही अपनी रणनीति तैयार कर ली है ताकि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार का मानसून सत्र काफी अहम रहने वाला है क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण विधेयकों के अलावा विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है। सरकार जहां अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी, वहीं विपक्ष जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसे में आगामी मानसून सत्र राजनीतिक और विधायी दोनों दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

## ISRO वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर सरकार ने लगाई रोक

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन को समय पर पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। अंतरिक्ष विभाग ने इसरो के प्रमुख केंद्रों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि गगनयान और अन्य राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं पर कार्यरत वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों के इस्तीफे या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) के आवेदनों को फिलहाल स्वीकार न किया जाए। यह निर्णय ऐसे समय लिया गया है जब पिछले कुछ महीनों में 100 से अधिक वैज्ञानिकों और तकनीकी अधिकारियों द्वारा इस्तीफा या वीआरएस के लिए आवेदन दिए जाने की खबरें सामने आई थीं।मंगलवार को जारी किए गए आधिकारिक ज्ञापन में विशेष रूप से ग्रुप 'ए' के वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों का उल्लेख किया गया है। सरकार का मानना है कि गगनयान जैसे मिशनों में वर्षों का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों की अचानक कमी से परियोजनाओं की समयसीमा और गुणवत्ता दोनों प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए जब तक इन महत्वपूर्ण मिशनों का प्रमुख चरण पूरा नहीं हो जाता, तब तक अनुभवी वैज्ञानिकों की सेवाएं बनाए रखना आवश्यक है। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसके तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को स्वदेशी तकनीक से विकसित यान के जरिए अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी की जा रही है। इस मिशन को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इसके अलावा चंद्रयान, आदित्य-एल1 और भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशनों जैसी परियोजनाओं में भी अनुभवी वैज्ञानिकों की अहम भूमिका है।

## शरजील इमाम की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगा पुलिस का जवाब

फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े कथित बड़ी साजिश के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति विकास महाजन की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस से विस्तृत जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख निर्धारित की।शरजील इमाम ने ट्रायल कोर्ट द्वारा 4 जुलाई को जमानत याचिका खारिज किए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनके वकीलों इब्राहिम और तालिब मुस्तफा ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल लंबे समय से न्यायिक हिरासत में हैं और मुकदमे की सुनवाई पूरी होने में अभी काफी समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को निष्पक्ष सुनवाई और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, इसलिए अदालत जमानत पर विचार करे।वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह मामला गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम)

अधिनियम यानी यूएपीए के तहत दर्ज गंभीर मामलों में शामिल है। पुलिस के अनुसार जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर शरजील इमाम की भूमिका बड़ी साजिश से जुड़ी हुई है और इसी आधार पर उनकी जमानत का विरोध किया गया है।सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले के तथ्यों पर कोई टिप्पणी किए बिना केवल दिल्ली पुलिस से जवाब दाखिल करने को कहा। अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही जमानत याचिका पर निर्णय लिया जाएगा। अब इस बहुचर्चित मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी, जब पुलिस अपना पक्ष अदालत के सामने रखेगी। दिल्ली दंगों से जुड़ा यह मामला लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया में है और देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि हाईकोर्ट का आगामी फैसला इस मामले की आगे की सुनवाई और जमानत से जुड़े कानूनी पहलुओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

# अमेरिका-ईरान टकराव और गहराया

## पहली बार दोनों देशों ने नागरिक ढांचे को बनाया निशाना

**स्थिति की गंभीरता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, चीन, रूस और कई खाड़ी देशों ने तत्काल संयम बरतने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि नागरिक ढांचे पर हमले अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून की भावना के विपरीत हैं और यदि दोनों पक्ष जल्द तनाव कम नहीं करते हैं तो इसका असर पूरे पश्चिम एशिया की स्थिरता पर पड़ सकता है।**

मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब एक नए और अधिक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है।17 जुलाई 2026 को दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव उस समय और गंभीर हो गया, जब पहली बार दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। अब तक संघर्ष मुख्य रूप से सैन्य ठिकानों, हथियार डिपो और रणनीतिक ठिकानों तक सीमित था, लेकिन हालिया घटनाक्रम ने पूरे क्षेत्र में बड़े युद्ध की आशंका को और बढ़ा दिया है।अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, ईरान समर्थित समूहों की ओर से क्षेत्र में स्थित अमेरिकी हितों और ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के भीतर ऐसे ठिकानों पर कार्रवाई की, जिन्हें वह सैन्य और रणनीतिक गतिविधियों से जुड़ा बता रहा है। हालांकि ईरान का आरोप है कि अमेरिकी हमलों में नागरिक बिजली ढांचे, संचार नेटवर्क और सार्वजनिक सुविधाओं को भी नुकसान पहुंचा है।ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कहा कि उसने अमेरिकी सैन्य हितों के साथ-साथ उन प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया है, जिन्हें वह अमेरिका के सैन्य अभियान में सहयोगी मानता है। दोनों देशों के दावों के बीच स्वतंत्र रूप से नुकसान की पूरी पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के अनुसार कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और आवश्यक सेवाओं पर असर पड़ा है। कुछ स्थानों पर नागरिकों के हताहत होने की भी खबरें सामने आई हैं।स्थिति की गंभीरता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, चीन, रूस और कई खाड़ी देशों ने तत्काल संयम बरतने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि नागरिक ढांचे पर हमले अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून की भावना के विपरीत हैं और यदि दोनों पक्ष जल्द तनाव कम नहीं करते हैं तो इसका असर पूरे पश्चिम एशिया की स्थिरता पर पड़ सकता है।इस बढ़ते संघर्ष का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है। तेल आपूर्ति बाधित होने की आशंका के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किए हैं और खाड़ी क्षेत्र में रह रहे विदेशी नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी है।विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिका और ईरान के बीच यह टकराव इसी तरह बढ़ता रहा, तो यह केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की सुरक्षा, वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है। फिलहाल दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में कूटनीतिक प्रयास तनाव कम करने में सफल होते हैं या क्षेत्र एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ता है।

### अमेरिका-ईरान तनाव का असर वैश्विक बाजार पर

अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बढ़ रहे सैन्य तनाव का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी साफ दिखाई देने लगा है।17 जुलाई 2026 को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया। ब्रेंट क्रूड का भाव पिछले एक महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड की कीमतों में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। ऊर्जा बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पश्चिम एशिया में हालात और बिगड़ते हैं, तो तेल की कीमतों में आगे भी तेजी बनी रह सकती है।विश्लेषकों के अनुसार निवेशकों को सबसे अधिक चिंता खाड़ी क्षेत्र में तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा को लेकर है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में शामिल हॉर्मुज जलडमरूमध्य से प्रतिदिन बड़ी मात्रा में कच्चे तेल और गैस का निर्यात होता है। यदि इस क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां बढ़ती हैं या जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है, तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर सीधा असर पड़ सकता है। तेल की कीमतों में तेजी के बाद एशिया और यूरोप के कई शेयर बाजारों में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। एयरलाइन, परिवहन और रसायन उद्योग से जुड़ी कंपनियों के शेयरों पर दबाव बना, जबकि ऊर्जा कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। निवेशकों ने सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख किया, जिससे सोने की कीमतों में भी मजबूती देखने को मिली। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) और कई वैश्विक वित्तीय संस्थानों ने कहा है कि यदि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लंबा खिंचता है, तो इसका असर केवल ऊर्जा बाजार तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि वैश्विक महंगाई, परिवहन लागत और औद्योगिक उत्पादन पर भी पड़ सकता है।

**केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की भारत 15 अगस्त 2027 से अपनी पहली बुलेट ट्रेन का पहला चरण शुरू करेगा**

## देशभर में मानसून सक्रिय कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

देशभर में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 17 जुलाई को जारी अपने ताजा पूर्वानुमान में उत्तर, मध्य, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र और सक्रिय मानसूनी ट्रफ के कारण वर्षा की गतिविधियां तेज हो गई हैं, जिससे कई राज्यों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका है।आईएमडी के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के कुछ हिस्सों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के अधिकांश राज्यों में तेज बारिश होने की संभावना है। कई क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए विभिन्न राज्य सरकारों ने जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील जिलों में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की टीमों को तैनात किया गया है। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन, बादल फटने और नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी की आशंका के मद्देनजर प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि यह बारिश खरीफ फसलों के लिए काफी लाभदायक साबित हो सकती है, क्योंकि कई इलाकों में अब तक सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई थी।

## राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में फेरबदल के बीच दूसरे दिन भी जारी रहे विरोध प्रदर्शन

यूक्रेन में 17 जुलाई 2026 को राजनीतिक घटनाक्रम ने नया मोड़ ले लिया। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा परिषद (National Security and Defense Council) में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया। सरकार ने इस कदम को राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में आवश्यक सुधार बताया है। हालांकि विपक्ष और नागरिक संगठनों ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं और इसे राजनीतिक नियंत्रण मजबूत करने की कोशिश करार दिया है।राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में बदलाव ऐसे समय किया गया है जब रूस के साथ जारी युद्ध, आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बना हुआ है। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बदलती सुरक्षा परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक तेज और प्रभावी बनाने के लिए यह पुनर्गठन किया गया है। नए अधिकारियों को साइबर सुरक्षा, रक्षा समन्वय और रणनीतिक योजनाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है।इसी बीच राजधानी कीव सहित कई शहरों में दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने, भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करने और महत्वपूर्ण फैसलों में संसद की भूमिका सुनिश्चित करने की मांग की। प्रदर्शन अधिकतर शांतिपूर्ण रहे, हालांकि कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हल्की झड़प की खबरें भी सामने आईं। यूरोपीय संघ और अमेरिका ने यूक्रेन के घटनाक्रम पर नजर बनाए रखते हुए कहा है कि युद्ध के दौरान राजनीतिक स्थिरता और लोकतांत्रिक संस्थाओं का मजबूत रहना बेहद जरूरी है। विश्लेषकों का मानना है कि सुरक्षा परिषद में किया गया यह फेरबदल आने वाले समय में यूक्रेन की रक्षा नीति और प्रशासनिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। वहीं लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन यह संकेत दे रहे हैं कि युद्ध के साथ-साथ सरकार को घरेलू राजनीतिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है।

## ईरान की अमेरिका को खुली चेतावनी, कहा- 'दो दिन में नहीं रुका युद्ध तो होगा पूर्ण हमला'

मध्य पूर्व में जारी भीषण संघर्ष के बीच ईरान ने अमेरिका को अब तक की सबसे गंभीर चेतावनी दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार मोहसेन रेज़ाई ने साफ तौर पर कहा है कि यदि अमेरिका ने अगले दो-तीन दिनों के भीतर अपनी सैन्य कार्रवाई नहीं रोकी, तो ईरान 'पूर्ण पैमाने पर हमले' के चरण में प्रवेश कर जाएगा। मोहसेन रेज़ाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में लिखा, "अगर अमेरिका अगले दो-तीन दिनों में युद्ध जारी रखता है, तो हम दुश्मन पर पूर्ण पैमाने पर हमले और उसे पूरी तरह खत्म करने के चरण में प्रवेश करेंगे।" उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि इस रणनीति के लागू होने के बाद ईरान केवल बराबर की जवाबी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा, और कोई भी राजनीतिक सीमा अमेरिकी सेनाओं को ईरान के आक्रामक हमलों से सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाएगी। इस बीच, एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, अमेरिका और ईरान ने मध्य पूर्व में अपने हमलों को तेज कर दिया है। होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पर नियंत्रण की लड़ाई तेज होने के साथ ही उन्होंने बुनियादी ढांचे और सैन्य ठिकानों को निशाना

बनाते हुए एक-दूसरे पर हमले किए। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने हमलों का विस्तार करते हुए और अधिक पुलों और ऊर्जा स्थलों को निशाना बनाया और ईरान के एक प्रमुख बंदरगाह पर एक टावर को गिरा दिया। यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की उन धमकियों के अनुरूप था जिनमें तेहरान पर उस जलमार्ग पर अपनी पकड़ ढीली करने का दबाव बनाने की बात कही गई थी, जो दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। जवाबी कार्रवाई में, ईरान ने मध्य पूर्व में अमेरिका के सहयोगी देशों पर मिसाइलें दागीं, जिनमें युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला कतर और कुवैत शामिल हैं। कुवैत में, रेगिस्तानी देश के पानी के अलवणीकरण संयंत्रों (water desalination plants) में से एक क्षतिग्रस्त हो गया। इस क्षेत्र ने जलडमरूमध्य पर नियंत्रण पर केंद्रित संघर्ष में कई दिनों तक लगातार हमले झेले हैं, और अंतरिम युद्धविराम के टूटने से चार महीने से अधिक समय पहले शुरू हुए इस युद्ध का कोई स्पष्ट अंत नजर नहीं आ रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने शुक्रवार देर रात कहा कि उसने ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करने के उद्देश्य से लगातार सातवीं रात हमले किए।

## संपादक की कलम से

देश में आधारभूत ढांचे के विकास को लेकर एक बार फिर बड़ा संदेश सामने आया है। प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान और गुजरात में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास केवल दो राज्यों तक सीमित घटना नहीं है, बल्कि यह भारत की विकास रणनीति का संकेत भी है। सड़क, रेल, ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल, मेट्रो और हवाई अड्डों जैसी परियोजनाएं किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती हैं। यदि इनका समय पर और प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो, तो रोजगार सृजन, निवेश और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलती है।पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि की है। इसका असर राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे आधुनिकीकरण, बंदरगाहों और ऊर्जा क्षेत्र में दिखाई भी दे रहा है। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह निवेश आवश्यक है, क्योंकि बेहतर कनेक्टिविटी से उद्योगों की लागत घटती है, व्यापार बढ़ता है और आम नागरिकों का जीवन भी आसान होता है।हालांकि केवल परियोजनाओं की घोषणा कर देना ही पर्याप्त नहीं है। देश ने ऐसे अनेक उदाहरण भी देखे हैं, जहां बड़े-बड़े शिलान्यास वर्षों तक अधूरे पड़े रहे या लागत कई गुना बढ़ गई। इसलिए किसी भी परियोजना की वास्तविक सफलता उसके समयबद्ध निर्माण, गुणवत्ता और जनता को मिलने वाले प्रत्यक्ष लाभ से तय होती है। सरकार की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि घोषित योजनाएं निर्धारित समय के भीतर पूरी हों और उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।विपक्ष का यह दायित्व भी है कि वह केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित न रहे, बल्कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन, पारदर्शिता और वित्तीय जवाबदेही पर रचनात्मक निगरानी रखे। लोकतंत्र में विकास और जवाबदेही एक-दूसरे के पूरक हैं। जहां सरकार विकास का रोडमैप तैयार करती है, वहीं विपक्ष और स्वतंत्र संस्थाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि सार्वजनिक धन का उपयोग सही दिशा में हो।भारत आज विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। ऐसे समय में आधुनिक बुनियादी ढांचे में निवेश भविष्य की आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ सुशासन, पारदर्शिता और पर्यावरणीय संतुलन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। विकास का उद्देश्य केवल आंकड़ों में वृद्धि नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर में वास्तविक सुधार होना चाहिए।सरकार और विपक्ष दोनों को यह समझना होगा कि विकास परियोजनाएं चुनावी राजनीति का साधन बनने के बजाय राष्ट्रीय निर्माण का माध्यम बनें। यदि योजनाओं का लाभ समय पर जनता तक पहुंचे, रोजगार बढ़े और संसाधनों का पारदर्शी उपयोग हो, तभी भारत का विकास मॉडल वास्तव में समावेशी और टिकाऊ कहलाएगा।

# जौहर यूनिवर्सिटी विवाद गरमाया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार को घेरा

**अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उत्तर प्रदेश सरकार और रामपुर विकास प्राधिकरण से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। बोर्ड ने मांग की है कि विध्वंस नोटिस तत्काल वापस लिया जाए, निर्माण से जुड़े कानूनी या तकनीकी विवादों का समाधान बातचीत और विधिक प्रक्रिया के जरिए किया जाए तथा जौहर विश्वविद्यालय जैसे शिक्षण संस्थान के संरक्षण और संचालन को सुनिश्चित किया जाए।**

अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) द्वारा मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की 38 इमारतों को लेकर जारी किए गए विध्वंस नोटिस पर कड़ी आपत्ति जताई है। बोर्ड ने इस कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण, दुर्भाविनापूर्ण और अन्यायपूर्ण बताते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से नोटिस को तत्काल वापस लेने और प्रस्तावित ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। बोर्ड का कहना है कि इस मामले का समाधान विध्वंस जैसी कठोर कार्रवाई के बजाय कानूनी प्रक्रिया और संवाद के माध्यम से किया जाना चाहिए। AIMPLB के प्रवक्ता डॉ. एसक्यूआर इलियास ने जारी बयान में कहा कि यह मामला केवल एक शिक्षण संस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि मुस्लिम समुदाय की शैक्षिक प्रगति से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां सरकारें लंबे समय से मुसलमानों के शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने में अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सकीं, वहीं समाज के सहयोग और वर्षों की मेहनत से स्थापित शिक्षण संस्थानों को प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। डॉ. इलियास ने दावा किया कि जौहर विश्वविद्यालय के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पूर्व मंत्री आजम खान के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना को दर्शाती है। उनका कहना था कि इस तरह के कदम न केवल एक व्यक्ति या संस्थान को प्रभावित करते हैं, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में समुदाय की भागीदारी और विकास की संभावनाओं को भी कमजोर करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रामपुर विकास प्राधिकरण के उस दावे को भी खारिज किया, जिसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय की 40 इमारतों में से 38 का निर्माण आवश्यक स्वीकृतियों के बिना किया गया। बोर्ड के अनुसार, विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि संबंधित इमारतों का निर्माण उस समय हुआ था, जब यह क्षेत्र रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं था। ऐसे में उस समय RDA से भवन मानचित्र या निर्माण स्वीकृति लेना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं था।डॉ. इलियास ने कहा कि यदि निर्माण से जुड़े किसी प्रकार के तकनीकी या कानूनी मुद्दे हैं, तो उनका समाधान निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्षों की मेहनत, जनसहयोग और बड़े निवेश से तैयार हुए एक विश्वविद्यालय की 38 इमारतों को ध्वस्त करने जैसी कार्रवाई न केवल असंगत है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकती है। बोर्ड का कहना है कि अगर विश्वविद्यालय की इमारतों को गिराया जाता है तो इसका असर केवल एक संस्थान या किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं रहेगा। उनके अनुसार, इस प्रकार की कार्रवाई देश की शैक्षिक संपत्तियों को अपूरणीय क्षति पहुंचाएगी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नकारात्मक संदेश देगी।

# टीएमसी छोड़ने वाले तीन पूर्व सांसद भाजपा के टिकट पर राज्यसभा पहुंचे

पश्चिम बंगाल की राजनीति में 17 जुलाई 2026 को बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला, जब तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) छोड़कर हाल ही में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए तीन पूर्व सांसद—सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बड़ाइक—भाजपा के उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब बंगाल में अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो रही हैं और भाजपा तथा टीएमसी के बीच राजनीतिक मुकाबला लगातार तीखा होता जा रहा है।इन नेताओं ने कुछ ही दिन पहले टीएमसी से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थामा था। इसके तुरंत बाद भाजपा द्वारा उन्हें राज्यसभा उम्मीदवार बनाया जाना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। निर्विरोध निर्वाचन के बाद भाजपा ने इसे पश्चिम बंगाल में अपनी बढ़ती राजनीतिक स्वीकार्यता का संकेत बताया और कहा कि टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं का पार्टी छोड़ना इस बात का प्रमाण है कि राज्य में ममता बनर्जी के नेतृत्व को लेकर असंतोष बढ़ रहा है।दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा के दावों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी अपने संगठन को और मजबूत करने में जुटी है तथा कुछ नेताओं के जाने से उसके जनाधार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। टीएमसी नेताओं का कहना है कि जनता का विश्वास अब भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार के साथ है। पार्टी ने इसे भाजपा की राजनीतिक रणनीति करार देते हुए कहा कि बंगाल की जनता आगामी चुनाव में इसका जवाब देगी।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्यसभा चुनाव का यह परिणाम केवल संसदीय प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर पश्चिम बंगाल की आगामी राजनीतिक रणनीतियों पर भी पड़ सकता है। हाल के दिनों में दोनों दलों के बीच नेताओं के दल-बदल की घटनाएं तेज हुई हैं, जिससे राज्य का राजनीतिक माहौल और अधिक गर्म हो गया है। भाजपा अब इस घटनाक्रम को अपने संगठनात्मक विस्तार और राजनीतिक मजबूती के रूप में पेश कर रही है, जबकि टीएमसी इसे सीमित प्रभाव वाली घटना बता रही है। ऐसे में आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह राजनीतिक फेरबदल विधानसभा चुनाव की दिशा और राज्य की राजनीति पर कितना असर डालता है। फिलहाल, तीन पूर्व टीएमसी सांसदों का भाजपा के टिकट पर राज्यसभा पहुंचना पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है और इसने राज्य की सियासत को नई बहस दे दी है।

# संसद के मानसून सत्र से पहले पांच नए विधेयकों की तैयारी FCRA संशोधन भी एजेंडे में

केंद्र सरकार ने 18 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र से पहले अपनी विधायी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। सरकार इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी में है, जिनका उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कानूनों में बदलाव करना और विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाना बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इस बार सरकार पांच नए विधेयक संसद में पेश कर सकती है, जिनमें सबसे अधिक चर्चा विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) में प्रस्तावित संशोधन और 'वंदे मातरम्' के अपमान को दंडनीय अपराध बनाने से जुड़े विधेयक की हो रही है।सरकारी सूत्रों का कहना है कि एफसीआरए संशोधन का उद्देश्य विदेशी फंड प्राप्त करने वाले संगठनों की कार्यप्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाना और धन के उपयोग की निगरानी को और प्रभावी बनाना है। सरकार का मानना है कि राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए विदेशी फंडिंग से जुड़े नियमों को समय-समय पर अद्यतन करना आवश्यक है। हालांकि विपक्षी दलों और कुछ सामाजिक संगठनों ने पहले ही संकेत दिया है कि वे इस प्रस्तावित संशोधन का विरोध कर सकते हैं और इसे नागरिक संगठनों की स्वतंत्रता से जोड़कर देख रहे हैं।दूसरी ओर, 'वंदे मातरम्' के सम्मान से जुड़े प्रस्तावित विधेयक को लेकर भी राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। सरकार का तर्क है कि राष्ट्रीय प्रतीकों और राष्ट्रीय भावनाओं के सम्मान को कानूनी संरक्षण दिया जाना चाहिए, जबकि विपक्ष का कहना है कि इस तरह के कानून पर व्यापक चर्चा और सभी दलों की सहमति जरूरी है।सूत्रों के अनुसार, लंबे समय से चर्चा में रहे परिसीमन (Delimitation) से जुड़े किसी बड़े विधेयक को फिलहाल इस सत्र के एजेंडे में शामिल नहीं किया गया है। इससे दक्षिण और उत्तर भारत के कई राज्यों में चल रही राजनीतिक चर्चाओं को फिलहाल विराम मिल सकता है। विपक्ष ने भी मानसून सत्र के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है। महंगाई, बेरोजगारी, कृषि, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और विभिन्न राज्यों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार संसद का मानसून सत्र विधायी कार्यों के साथ-साथ तीखी राजनीतिक बहस और टकराव का भी गवाह बन सकता है।

# PF खाताधारकों के लिए नया नियम

## UAN से जुड़े सभी काम अब UMANG ऐप से

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने लगभग एक सप्ताह तक चले निर्धारित तकनीकी अपग्रेड के बाद अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल को नए स्वरूप में फिर से शुरू कर दिया है। सॉफ्टवेयर और डेटाबेस के व्यापक आधुनिकीकरण के बाद पोर्टल का इंटरफेस पूरी तरह बदल गया है। इसके साथ ही ईपीएफओ ने अपनी कई डिजिटल सेवाओं में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिनका सीधा असर देशभर के करोड़ों पीएफ खाताधारकों पर पड़ेगा। संगठन का कहना है कि इन परिवर्तनों का उद्देश्य ऑनलाइन सेवाओं को अधिक सुरक्षित, तेज और पारदर्शी बनाना है। सबसे बड़ा बदलाव यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से जुड़ी सेवाओं में किया गया है। अब EPFO की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से न तो ही नया UAN जनरेट किया जा सकेगा। इन दोनों सुविधाओं को पूरी तरह भारत सरकार के UMANG (Unified Mobile Application for New-age Governance) ऐप पर स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके साथ ही सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। ईपीएफओ का मानना है कि इससे पहचान सत्यापन अधिक सुरक्षित होगा और फर्जीवाड़े की संभावनाएं कम होंगी।नए सिस्टम के तहत यदि किसी कर्मचारी का UAN अभी तक सक्रिय नहीं है या नया UAN बनवाना है, तो उसे UMANG ऐप में जाकर EPFO Services सेक्शन के 'UAN Allotment and Activation' विकल्प का उपयोग करना होगा। यहां आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करने के बाद आवश्यक जानकारी भरकर UAN सक्रिय या नया UAN प्राप्त किया जा सकेगा। जिन कर्मचारियों का पीएफ खाता पहले से है लेकिन उन्हें अभी तक UAN आवंटित नहीं हुआ है, वे भी UMANG ऐप के माध्यम से अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर सत्यापित कर नया UAN प्राप्त कर सकते हैं। नया UAN उनके मौजूदा पीएफ खाते से स्वतः लिंक कर दिया जाएगा।हालांकि UAN से जुड़ी सेवाओं को UMANG ऐप पर स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन 'Know Your UAN' सुविधा को पहले की तुलना में अधिक सरल बनाया गया है। यदि कोई सदस्य अपना UAN भूल जाता है तो वह नए पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नंबर, आवश्यक पहचान दस्तावेज और ओटीपी सत्यापन के माध्यम से आसानी से अपना UAN प्राप्त कर सकेगा। ईपीएफओ ने यह भी स्पष्ट किया है कि डेथ क्लेम की ऑनलाइन सुविधा पहले की तरह यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर ही उपलब्ध रहेगी। इसके लिए नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी के पास आधार से लिंक मोबाइल नंबर, बैंक खाते का विवरण, रद्द चेक या पासबुक की प्रति, सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा आवश्यकता अनुसार आयु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा। सभी दस्तावेज केवल पीडीएफ प्रारूप में स्वीकार किए जाएंगे और प्रत्येक फाइल का आकार 2 एमबी से कम होना चाहिए। साथ ही फाइल के नाम में किसी प्रकार का स्पेस नहीं होना चाहिए। ईपीएफओ के अनुसार यह अपग्रेड संगठन की डिजिटल सेवाओं को आधुनिक बनाने और डेटाबेस को अधिक मजबूत एवं सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि संगठन ने यह भी स्वीकार किया है कि सिस्टम के स्थिरीकरण की प्रारंभिक दो सप्ताह की अवधि में ऑनलाइन अनुरोधों और क्लेम के निस्तारण में सामान्य से अधिक समय लग सकता है, क्योंकि इस दौरान अतिरिक्त सत्यापन और वैलिडेशन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ईपीएफओ ने सदस्यों से अपील की है कि वे पीक आवर्स में बार-बार लॉगिन करने या एक ही अनुरोध को कई बार सबमिट करने से बचें, ताकि सिस्टम पर अनावश्यक दबाव न पड़े और सभी सेवाएं सुचारू रूप से संचालित हो सकें।

## बिहार के 211 डिग्री कॉलेजों में नहीं शुरू हो सकी पढ़ाई, अधूरी तैयारियां बनीं वजह

बिहार में उच्च शिक्षा व्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। राज्य के 211 नए डिग्री कॉलेजों में अधूरी तैयारियों के कारण शैक्षणिक सत्र समय पर शुरू नहीं हो सका। इन कॉलेजों में भवन, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, फर्नीचर और शिक्षकों की नियुक्ति जैसी बुनियादी व्यवस्थाएं पूरी नहीं होने के कारण छात्रों को इंतजार करना पड़ रहा है।राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के उद्देश्य से इन कॉलेजों की स्थापना की थी, लेकिन आवश्यक संसाधनों की कमी के कारण अधिकांश संस्थान अभी पूरी तरह संचालन के लिए तैयार नहीं हैं। इससे हजारों विद्यार्थियों के प्रवेश और नियमित पढ़ाई पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।शिक्षा विभाग का कहना है कि अधूरे कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। भवन निर्माण, उपकरणों की उपलब्धता और शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है ताकि आगामी सत्र में सभी कॉलेज पूरी क्षमता के साथ संचालित हो सकें।शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि केवल नए कॉलेज खोलना पर्याप्त नहीं है। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए आधारभूत ढांचा, योग्य शिक्षक और आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं भी समय पर उपलब्ध कराना जरूरी है। छात्रों और अभिभावकों को उम्मीद है कि सरकार जल्द आवश्यक तैयारियां पूरी कर इन कॉलेजों में नियमित शिक्षण कार्य शुरू कराएगी।

## मोहम्मद नवाज़ को एंटी-डोपिंग नियमों के उल्लंघन के लिए तीन महीने के लिए निलंबित किया गया

## महान ऑलराउंडर सर गारफील्ड सोबर्स का निधन

क्रिकेट जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हरफनमौला खिलाड़ियों में शामिल सर गारफील्ड सोबर्स का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन से विश्व क्रिकेट ने एक ऐसे खिलाड़ी को खो दिया है, जिसने अपने शानदार खेल, नेतृत्व और रिकॉर्डों के दम पर खेल के इतिहास में हमेशा के लिए अपनी अलग पहचान बनाई। बता दें कि सर गारफील्ड सोबर्स का जन्म कैरेबियाई देश बारबाडोस में हुआ था। उन्होंने बहुत कम उम्र में अपनी प्रतिभा से सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया था। महज 16 वर्ष की आयु में उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण किया, जबकि 18 वर्ष की उम्र में वेस्टइंडीज की राष्ट्रीय टीम के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। मौजूद जानकारी के अनुसार सर गारफील्ड सोबर्स ने वर्ष 1954 से 1974 के बीच वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच खेले। इस दौरान उन्होंने 57.78 की शानदार औसत से 8,032 रन बनाए। इसके अलावा उन्होंने एक एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबला भी खेला। उनकी बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी की बहुमुखी प्रतिभा भी उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती थी। वह बाएं हाथ से पारंपरिक स्पिन, कलाई की स्पिन और मध्यम गति की गेंदबाजी करने में समान रूप से सक्षम थे। गौरतलब है कि वर्ष 1958 में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने अपने करियर का पहला टेस्ट शतक बनाया और उसे 365 रन की ऐतिहासिक पारी में बदल दिया। उस समय यह टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर था। बाद में वर्ष 1994 में ब्रायन लारा ने 375 रन बनाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। हालांकि पहली टेस्ट शतकीय पारी में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड आज भी सर गारफील्ड सोबर्स के नाम दर्ज है।

## लॉर्ड्स में तीसरा वनडे हो सकता है रोहित शर्मा का अंतिम मुकाबला

अटकलें लगाई जा रही है कि इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में होने वाला तीसरा वनडे मैच रोहित शर्मा का आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच होगा और पूर्व भारतीय क्रिकेटर पार्थिव पटेल को उम्मीद है कि वह इस मैच में शतक जड़कर अपने आलोचकों को करारा जवाब देंगे। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय चयनकर्ताओं ने रोहित को बता दिया है कि दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में 2027 में होने वाले विश्व कप के लिए उन्हें टीम में जगह नहीं मिलेगी। इससे रविवार को होने वाले मैच के बाद रोहित के संन्यास की घोषणा करने या उन्हें स्थायी रूप से टीम से बाहर किए जाने की संभावना पैदा हो गई है। वह पहले ही टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। पटेल ने जियोस्टार से कहा, "'अगर लॉर्ड्स में खेला गया वनडे मैच वाकई रोहित शर्मा के अंतरराष्ट्रीय करियर का आखिरी मैच है, तो वह शतक के साथ विदाई लेना चाहेंगे। वह ऐसा करने में पूरी तरह सक्षम हैं। हमने उनके पूरे करियर में देखा है कि दो-तीन मैच में कम स्कोर बनाने के बाद वह अक्सर बड़ा स्कोर बनाते हैं।" रोहित ने दूसरे वनडे में 47 गेंद पर 26 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली। पटेल ने कहा, "विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच हमेशा से ही निरंतरता का अंतर रहा है। रोहित हर मैच में बड़ा स्कोर नहीं बनाते, लेकिन जब भी बनाते हैं तो दमदार पारी खेलते हैं। इस मैच में वह सहज नहीं दिखे।" पटेल ने स्वीकार किया कि कार्डिफ में पिच की अनियमित उछाल से रोहित परेशान थे और किसी भी समय लय हासिल नहीं कर सके। उन्होंने कहा, " यह उनके लिए अपने आलोचकों को चुप कराने का एक और मौका है। वह पहले भी कई बार ऐसा कर चुके हैं। अगर लॉर्ड्स वनडे वास्तव में उनका आखिरी मैच है तो मुझे उम्मीद है कि वह ऐसी पारी खेलेंगे जिसे लोग लंबे समय तक याद रखेंगे।

## संन्यास की खबरों के बीच BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने दिया बड़ा बयान

भारतीय क्रिकेट में इन दिनों सबसे बड़ी चर्चा रोहित शर्मा के इंटरनेशनल क्रिकेट में फ्यूचर को लेकर हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सेलेक्टर्स अब 2027 वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए नई टीम तैयार करने की दिशा में बढ़ चुके हैं, इस वजह से 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाने वाला तीसरा वनडे रोहित के इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच हो सकता है। इसी बीच बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने रोहित शर्मा के संन्यास पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि लॉर्ड्स वनडे रोहित के करियर का आखिरी इंटरनेशनल मैच नहीं होगा। बीसीसीआई (BCCI) सचिव देवजीत सैकिया ने न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से कहा कि मीडिया में रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर जो भी बातें चल रही हैं, वे सिर्फ अफवाहें हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है कि रविवार को लॉर्ड्स में होने वाला मैच रोहित का आखिरी मैच होगा। रोहित भारतीय वनडे टीम के अहम खिलाड़ी हैं और जब तक टीम को उनकी जरूरत है, वह देश के लिए खेलते रहेंगे। आसान शब्दों में कहें तो, लॉर्ड्स वनडे उनका आखिरी मैच नहीं है। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। उन्होंने शुरुआती दो वनडे मैचों में केवल 11 और 26 रन ही बनाए। आपको बता दें कि पिछले साल ही उनसे वनडे टीम की कप्तानी ले ली गई थी और शुभमन गिल को नया कप्तान बनाया गया था। इस फैसले से ही साफ होने लगा था कि सिलेक्टर्स अब आगे के लिए नई और युवा टीम तैयार करना चाहते हैं। रोहित शर्मा पहले ही दो बड़े फॉर्मेट छोड़ चुके हैं उन्होंने 29 जून 2024 को भारत को टी-20 वर्ल्ड कप जिताने के बाद टी-20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था और फिर 7 मई 2025 को इंग्लैंड दौरे की शुरुआत से ठीक पहले टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया था। रोहित शर्मा भारत के सबसे कामयाब कप्तानों में से एक हैं। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची थी। उन्होंने टीम को मैच की पहली गेंद से ही आक्रामक होकर खेलने का नया तरीका सिखाया, जिसने वनडे क्रिकेट में भारत का अंदाज पूरी तरह बदल दिया। इसी नए टेम्पलेट की बदौलत भारत ने 2024 का टी-20 वर्ल्ड कप जीता और फिर 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी भी अपने नाम की।

### इंटरनेट पर वायरल वीडियो ने खोली पोल!

# वांगचुक के नाम पर झूठ क्यों बोल रहे आमिर?

**20 दिन** से भूख हड़ताल पर बैठे इंजीनियर और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पर इस समय पूरे देश की नजरें लगी हैं. हाल ही में सुपरस्टार आमिर खान से सोनम की भूख हड़ताल को लेकर सवाल किया गया. आमिर की पॉपुलर फिल्म 3 इडियट्स में उनका किरदार सोनम से इंस्पायर्ड बताया जाता रहा है, लेकिन आमिर ने इस बात से साफ इनकार कर दिया. आमिर ने ये भी कहा कि वो 3 इडियट्स से पहले फिल्म के राइटर्स या वो खुद सोनम को नहीं जानते थे. अब सोशल मीडिया ने आमिर के इस दावे का एक्स-रे कर डाला है और एक वायरल वीडियो में सामने आया है कि वो 3 इडियट्स के शूट

से पहले एक अवॉर्ड शो का हिस्सा थे, जिसमें सोनम को उनके काम के लिए 'रियल हीरोज' अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने सोनम के एक टेड टॉक वीडियो का क्लिप शेयर किया है, जिसमें वो आमिर से अपनी मुलाकात का जिक्र करते नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं, इस टेड टॉक में सोनम ने उस अवॉर्ड शो का क्लिप भी चलाया था जिसमें वो अवॉर्ड लेते नजर आ रहे हैं. उनके सामने की तरफ बैठे मेहमानों में आमिर खान अपनी पूर्व पत्नी किरण राव के साथ बैठे नजर आ रहे हैं.

## गोविंदा का नाम सुनने को तैयार नहीं सुनीता

गोविंदा 7 साल बाद फिल्म 'रूपा' से हिंदी सिनेमा में कमबैक करने जा रहे हैं. इस सोमवार को उन्होंने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी फिल्म के बारे में बताया. कमबैक फिल्म से वो एक्ट्रेस रानी स्वर्णकार को बॉलीवुड में लॉन्च कर रहे हैं. गोविंदा को जो कहना था उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया. लोगों को इंतजार सुनीता आहूजा के रिएक्शन का था.

## हिट होगी 'रामायण', आशुतोष राणा बोले- हम राम के बच्चे

रणबीर कपूर की रामायण एक बार फिर चर्चा में आ गई है. 18 जुलाई को दिल्ली में इसका ग्रैंड इवेंट रखा गया है, जिसमें फिल्म की पूरी कास्ट शामिल होकर अपने प्रमोशन की शुरुआत करेगी. फिर 24 जुलाई को सैन डिएगो में कॉमिक-कॉन के अंदर रामायण का ट्रेलर वर्ल्ड प्रीमियर किया जाएगा. रामायण फिल्म पर काफी समय से बातचीत जारी है. जबसे इसका पहला टीजर सामने आया, तबसे लोग डरे हुए हैं कि कहीं ये फिल्म भी खराब ना निकल जाए.

# असहमति जताने की आजादी, जूनियर से नहीं मंगा सकते चाय

विदेश में नौकरी करने का सपना बहुत से लोग देखते हैं. अच्छी सैलरी के साथ-साथ वहां के वर्क कल्चर को भी लोग काफी पसंद करते हैं. अब जर्मनी में रहने वाली एक भारतीय महिला ने स्विट्जरलैंड के ऑफिसों की कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताया है, जिन्हें सुनकर भारत के कई लोगों को हैरानी हो सकती है. उनकी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग अलग-अलग देशों के वर्क कल्चर की तुलना कर रहे हैं. जर्मनी में रहने वाली प्रोडक्ट मैनेजर सिमरन खोखा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की. उन्होंने बताया कि उनकी एक दोस्त स्विट्जरलैंड की एक कंपनी में काम करती है.

उसी दोस्त से मिली जानकारी के आधार पर उन्होंने वहां के ऑफिस कल्चर की 12 खास बातें लोगों के साथ साझा कीं. सिमरन ने कहा कि यह सिर्फ अच्छी सैलरी का मामला नहीं है, बल्कि वहां काम करने का तरीका पूरी तरह अलग है. वहां कर्मचारियों की इज्जत, समय की कीमत और वर्क-लाइफ बैलेंस को बहुत महत्व दिया जाता है.

# कभी बॉम्बे प्रांत का हिस्सा थे ये खाड़ी देश!

**कभी** मिडिल ईस्ट और खाड़ी देश भारत का हिस्सा था. यह सुनकर थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन यमन, बहरीन, ओमान, यूएई, ये सभी इलाके ब्रिटिश इंडिया के अंदर आते थे और मिडल ईस्ट के ये देश भारत के बॉम्बे प्रांत का हिस्सा माने जाते थे. इन देशों में 1960 के दशक तक भारतीय रुपये चलते थे. ब्रिटेन से आजादी मिलने के बाद तक इन देशों में भारतीय रुपये का दबदबा था.

बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक, अदन से कुवैत तक फैले अरब संरक्षित इलाके पर दिल्ली से शासन किया जाता था, जिसकी देखरेख भारतीय राजनीतिक सेवा द्वारा की जाती थी. भारतीय सैनिकों द्वारा पुलिसिंग की जाती थी और जो भारत के वायसराय के प्रति जवाबदेह थे.

आधुनिक यमन के अदन तक भारतीय पासपोर्ट जारी किए जाते थे, जो भारत के सबसे पश्चिमी बंदरगाह के रूप में कार्य करता था और बॉम्बे प्रांत के हिस्से के रूप में प्रशासित था.

जब महात्मा गांधी ने 1931 में इस शहर का दौरा किया, तो उन्होंने पाया कि कई युवा अरब खुद को भारतीय राष्ट्रवादी मानते थे. 1920 के दशक तक, राजनीति में बदलाव आने लगा था. भारतीय राष्ट्रवादियों ने भारत को एक साम्राज्यवादी संरचना के रूप में नहीं, बल्कि महाभारत की भौगोलिक पृष्ठभूमि से जुड़े एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में देखना शुरू कर दिया था.

# तीसरी शादी पर ट्रोलिंग, आमिर ने तोड़ी चुप्पी

**बॉलीवुड** परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने 61 साल की उम्र में गौरी स्प्रैट संग घर बसाया. ये आमिर की तीसरी शादी है, आमिर की तीसरी शादी को लेकर चारों ओर बवाल मचा हुआ है. बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठनों ने उनपर लव जिहाद का आरोप लगाया. उन्हें 'लव जिहाद' का 'ब्रांड एंबेसडर' बताया जा रहा है. उनके खिलाफ फतवा भी जारी हुआ है. अब आमिर ने उनकी तीसरी शादी को लेकर उन्हें ट्रोल करने वालों को जवाब दिया है. आइए जानते हैं कि आमिर ने अपनी वेडिंग को लेकर क्या कहा. शादी को लेकर ट्रोलिंग झेल रहे आमिर ने डेक्कन क्रॉनिकल संग बातचीत में कहा कि

सच्चाई ये है कि हमारा परिवार बहुत मिलनसार और सबको साथ लेकर चलने वाला है. मेरी दोनों बहनों की शादी हिंदुओं से हुई है. मेरी बेटी की शादी भी एक हिंदू से हुई है. मेरे चचेरे भाई मंसूर ने एक ईसाई महिला से शादी की है. गौरी, रीना और किरण ने मुझसे शादी करते समय अपना धर्म नहीं बदला, क्योंकि हमारी शादी सिविल मैरिज थी.

# प्रधानमंत्री मोदी ने किया ऐशबाग जंक्शन का लोकार्पण,

# 24.13 करोड़ से हुआ कायाकल्प

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित ऐशबाग जंक्शन का ऑनलाइन लोकार्पण किया। 24.13 करोड़ रुपये की लागत से विकसित स्टेशन में आधुनिक प्रतीक्षालय, फुटओवर ब्रिज, वाटर कूलर, प्लेटफॉर्म शेड और बेहतर यात्री सुविधाएं जोड़ी गई हैं। स्टेशन को अवध की सांस्कृतिक वास्तुकला के अनुरूप नया स्वरूप दिया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 75 रेलवे स्टेशनों का शुक्रवार को ऑनलाइन लोकार्पण किया. इन सभी स्टेशनों का भव्य पुनर्विकास केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'अमृत भारत स्टेशन स्कीम' के तहत किया गया है. इन पुनर्विकसित स्टेशनों की सूची में पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल का ऐतिहासिक ऐशबाग जंक्शन भी प्रमुखता से शामिल है. लखनऊ जंक्शन-गोंडा जंक्शन रेल खंड पर स्थित ऐशबाग जंक्शन पूर्वोत्तर रेलवे का NSG-3 श्रेणी का एक बेहद महत्वपूर्ण स्टेशन माना जाता है. विकसित भारत के बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखकर रेल मंत्रालय ने ऐशबाग जंक्शन को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया है. इस स्टेशन को आधुनिक सुख-सुविधाओं से लैस करने के लिए कुल 24.13 करोड़ रुपये की भारी लागत से नया स्टेशन भवन डेवलप किया गया है. ऐशबाग स्टेशन पर वर्तमान में रोजाना 7,000 से अधिक रेल यात्रियों का सुगम आवागमन होता है. यह स्टेशन अपनी सीधी ट्रेन सेवाओं के माध्यम से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, जयपुर, कानपुर, गोरखपुर, भोपाल और सूरत जैसे देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. यात्रियों की सुविधा के लिए यहां पर पैदल उपरिगामी पुल, आधुनिक पूछताछ कार्यालय और एडवांस जनसंबोधन प्रणाली की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. स्टेशन पर 95 वर्ग मीटर में भव्य वेटिंग हॉल के साथ ही पुरुष और महिला यात्रियों के लिए अलग-अलग प्रतीक्षालय बनाए गए हैं. इसके अलावा यहाँ एक उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय और दो सर्वसुविधायुक्त रिटायरिंग रूम की सुविधा भी यात्रियों को मिलेगी. स्टेशन परिसर में 1,400 वर्ग मीटर में फैला बड़ा सर्कुलेटिंग एरिया और 1,500 मीटर लंबी चौड़ी एप्रोच रोड तैयार की गई है. यात्रियों को तेज धूप और भारी वर्षा से बचाने के लिए 860 वर्ग मीटर क्षेत्र में प्लेटफॉर्म छाजन (शेड) का निर्माण किया गया है. सभी प्लेटफॉर्मों पर यात्रियों के बैठने के लिए कुल 380 आरामदायक सीटें लगाई गई हैं. पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए यहाँ पानी के 65 नल और तीन अत्याधुनिक वाटर कूलर स्थापित किए गए हैं. बेहतरीन प्रकाश व्यवस्था और पर्याप्त पंखों के साथ ही यहाँ छह प्लेटफॉर्मों के माध्यम से कुल 27 ट्रेनों का नियमित स्टॉपेज सुनिश्चित किया गया है. स्थानीय अवध की वास्तुकला और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए मुख्य स्टेशन भवन के अग्रभाग में व्यापक सुधार किया गया है.

## हाईकोर्ट ने उठाए न्यायिक देरी पर सवाल, आरोपी को मिली अग्रिम जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अपहरण मामले में अहम जानकारी सामने आई तो जज चिंतित हो गए। जज ने कहा कि तारीख पे तारीख की स्थिति को देश की न्याय व्यवस्था की पहचान नहीं बनने दिया जा सकता। दरअसल, 2001 में एक पिता ने 15 साल की बेटी के अपहरण का आरोप एक व्यक्ति पर लगाया था। तब से मामले की सुनवाई चल रही थी। मामले में 24 साल बाद ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। असलियत यह है कि जिस पर अपहरण का आरोप था, उसने उसी लड़की से बाद में शादी कर ली। अब दोनों के 3 बच्चे भी हैं। न्यायालय ने कहा कि 24 साल पुराने मामले का इस तरह लंबित रहना और अब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना बेहद चिंताजनक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मुकदमे की सुनवाई में इतनी लंबी देरी को व्यक्ति के त्वरित सुनवाई के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया। इसके साथ ही बहराइच निवासी आरोपी अजय कुमार उर्फ छिनगी और अन्य को अग्रिम जमानत दे दी। अभियोजन के अनुसार, 12 दिसंबर 2001 को एक व्यक्ति ने अपनी 15 वर्षीय बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि अजय कुमार ने शादी की नीयत से उसका अपहरण किया है। पुलिस ने जांच पूरी कर अप्रैल 2002 में आरोपपत्र दाखिल कर दिया था।

# NEET UG 2026 में लखनऊ के छात्रों का जलवा, श्री नारायण ने हासिल की AIR 105

NEET यूजी 2026 के नतीजों में लखनऊ के छात्रों ने अपनी प्रतिभा का दम दिखाया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा गुरुवार देर रात घोषित परिणाम में लखनऊ में रहकर तैयारी करने वाले श्री नारायण मिश्रा ने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 105 हासिल की है। मूल रूप से महाराजगंज के रहने वाले श्री नारायण पिछले दो साल से ब ड़ी बहन के साथ लखनऊ में रहकर परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। वहीं, NTA की ओर से जारी परिणाम में शिवांश ने AIR 152, याशिर ने 157, मोहित ने 550, चिन्मय ने 569 और शावेज ने 738वीं रैंक हासिल की। नतीजे आने के बाद कोचिंग संस्थानों में जश्न का माहौल रहा। आकाश कोचिंग में टॉपर्स को विंटेज कार पर बैठाकर सम्मानित किया गया, जबकि डीजे और भांगड़ा के साथ उनकी सफलता का जश्न मनाया गया। रिजल्ट घोषित होने के बाद लाखों अभ्यर्थियों ने एक साथ NTA की वेबसाइट पर लॉग इन किया। अचानक बढ़े ट्रैफिक के कारण वेबसाइट कई बार धीमी पड़ गई और कुछ समय के लिए ठप भी रही। कई छात्रों और अभिभावकों ने सोशल मीडिया पर वेबसाइट न खुलने की शिकायतें भी साझा कीं। तकनीकी दिक्कत दूर होने के बाद अधिकांश अभ्यर्थी अपना परिणाम देख सके। नीट यूजी 2026 का री-एग्जाम 21 जून को आयोजित किया गया था। लखनऊ में परीक्षा के लिए 75 केंद्र बनाए गए थे, जहां 35,494 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। अब सफल छात्र मेडिकल और अन्य स्वास्थ्य विज्ञान पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे। NTA के अनुसार इस वर्ष 11.21 लाख अभ्यर्थियों का चयन एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए हुआ है। देशभर में 138 अभ्यर्थियों ने 720 में से 690 से अधिक अंक हासिल किए। इनमें 93% से अधिक छात्र पहली बार नीट परीक्षा में शामिल हुए थे। लगभग 99 % टॉपर्स की उम्र 17 से 19 वर्ष के बीच रही।

# 18 जुलाई से रफ्तार पकड़ेगा मानसून, लखनऊ में भारी बारिश के आसार

लखनऊ में सुबह से बादल छाए हुए हैं। दिन में मौसम साफ भी बना रहेगा। बादलों की गरज-चमक के साथ बारिश के आसार भी हैं। आज 18 जुलाई से एक सिस्टम यूपी में बन रहा है। इसके असर से मानसून लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में रफ्तार पकड़ सकता है। तापमान में गिरावट भी आएगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज लखनऊ का अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री के आसपास बना रहेगा। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री रहा। न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री रहा। अधिकतम आर्द्रता 84 फीसदी और न्यूनतम आर्द्रता 64 फीसदी रही। मौसम विभाग ने 22 जुलाई तक लगातार बारिश के आसार जताएं हैं। इस बीच 18 जुलाई के बाद मानसून पूरी तरह से फिर से सक्रिय होने की संभावना है। दिन में 3.2 मिलीमीटर बारिश हुई। जबकि, 15 जुलाई सुबह 8 बजे से 16 जुलाई सुबह 8 बजे तक 7.2 मिलीमीटर बारिश हुई। इस दौरान सामान्य सामान्य बारिश का औसत 7.1 मिलीमीटर है। मानसून में अभी तक 108.1 मिलीमीटर बरसात हुई है। जबकि, सामान्य बारिश का औसत 201.9 मिलीमीटर है। यह सामान्य से 48 फीसदी कम है।उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना है, जो धीरे-धीरे और मजबूत हो रहा है और उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। 18 जुलाई से इस सिस्टम के असर से लखनऊ समेत राज्य में मानसून रफ्तार पकड़ेगा। इसके बाद भारी बारिश होगी। तापमान में अच्छी-खासी गिरावट आएगी। पिछले कई दिनों से परेशान कर रही उमसभरी गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी।

### लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर नहीं रुक रही बाइकों की एंट्री, हादसों का खतरा बरकरार

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर बाइकसवारों की एंट्री बंद नहीं हो रही है। बाइकसवार कंफ्यूजन में एक्सप्रेसवे पर चढ़ जाते हैं। एंट्री करने पर उन्हें चेतावनी बोर्ड नहीं आता क्योंकि यह एक बड़े बोर्ड के पीछे छिपाकर रखा है। पुलिस की गाड़ी एंट्री पर खड़ी रहती है। कुछ पुलिसवाले भी बाइकसवारों को एक्सप्रेसवे पर चढ़ते देखते रहते हैं लेकिन रोकते नहीं हैं। वो इंतजार करते हैं बाइकसवारों के लौटने का। उसके बाद रॉन्ग साइड से लौट रहे बाइकसवारों को रोक-रोककर उनका चालान काटते हैं। गौरतलब है कि बुधवार शाम बंथरा थाना क्षेत्र में इसी एक्सप्रेसवे पर हुए एक सड़क हादसे में दो बाइक सवार युवकों की मौत हो गई थी। इस घटना के बावजूद प्रतिबंधित वाहनों की आवाजाही को प्रभावी ढंग से नहीं रोका जा रहा है। हादसे के बाद एनएचएआई ने दरोगा खेड़ा के पास एक छोटा चेतावनी बोर्ड लगाया है। हालांकि, स्थानीय लोगों का कहना है कि यह बोर्ड आकार में छोटा होने और बड़े दिशासूचक बोर्ड के कारण आसानी से दिखाई नहीं देता। दरोगा खेड़ा से एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद शिवपुरा और बनी के पास इंटरचेंज बने हैं, जहां टोल बैरियर लगे हैं।

# लखनऊ में अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 7 गिरफ्तार

लखनऊ में क्राइम ब्रांच ने सुशांत गोल्फ सिटी स्थित ओमैक्स आर-2 रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में चल रहे अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह अमेरिकी में रहने वाले लोगों को माइक्रोसॉफ्ट टेक्निकल सपोर्ट और अमेरिकी सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बनकर डराता था और उनसे गिफ्ट कार्ड, क्रिप्टोकरेंसी के जरिए रकम ऐंठता था। डीसीपी क्राइम अनिल कुमार यादव ने बताया कि आरोपी पहले विदेशी नागरिकों, खासकर अमेरिका के लोगों के कंप्यूटर में मैलवेयर या वायरस से जुड़े पॉप-अप भेजते थे। पॉप-अप पर दिए गए टोल-फ्री नंबर पर कॉल करने पर आरोपी खुद को माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बताते थे। इसके बाद पीड़ित को बताया जाता था कि उसका बैंक खाता, सोशल सिक्योरिटी नंबर या डिजिटल पहचान खतरे में है। जब पीड़ित डर जाता था तो कॉल दूसरे सदस्य को ट्रांसफर कर दी जाती थी, जो खुद को फेडरल ट्रेड कमीशन (FTC) या अन्य अमेरिकी एजेंसी का अधिकारी बताकर गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई का डर दिखाता था। विश्वास दिलाने के लिए ई-मेल से फर्जी FTC लेटर, आइडेंटिटी थेफ्ट रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, एनडीए और नकली कोर्ट ऑर्डर भी भेजे जाते थे। जांच में पता चला कि आरोपी टीम व्यूअर और अल्ट्रा व्यूअर जैसे रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर से पीड़ित के कंप्यूटर का नियंत्रण हासिल कर लेते थे। इसके बाद बैंकिंग और वित्तीय जानकारी लेकर उनसे अमेजन और वॉलमार्ट के गिफ्ट कार्ड खरीदवाते थे। बड़ी रकम वाले मामलों में अमेरिका में तय पते पर नकदी या सोना भी मंगवाया जाता था। गिरोह विभिन्न राज्यों से अंग्रेजी बोलने वाले बीपीओ कर्मचारियों की भर्ती करता था। कर्मचारियों को रहने की व्यवस्था भी कॉल सेंटर की ओर से उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन किसी को नियुक्ति पत्र या वैध अनुबंध नहीं दिया जाता था।

# ‘जय जगन्नाथ’ के जयघोष से गूंजा उन्नाव, हजारों श्रद्धालुओं ने खींचा रथ

उन्नाव में सार्वजनिक श्रीश्री जगन्नाथ जी रथयात्रा समिति की ओर से गुरुवार देर शाम भगवान श्रीजगन्नाथ, बलभद्र और मां सुभद्रा की 31वीं भव्य रथयात्रा निकाली गई। रात आठ बजे शुरू हुई यात्रा में तेज बारिश भी श्रद्धालुओं की आस्था को नहीं डिगा सकी। सैकड़ों श्रद्धालु "जय जगन्नाथ" के जयघोष के बीच रथ खींचते रहे। भजन-कीर्तन और शंखनाद से पूरा शहर भक्तिमय हो उठा। यात्रा देर रात करीब 11:45 बजे तक चली। रथयात्रा शुरू होने से पहले लक्ष्मी टॉकीज के सामने स्थित दिनेश्वर महादेव मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन-पूजन और विशेष आरती का आयोजन किया गया। इसके बाद भगवान श्रीजगन्नाथ, बलभद्र और मां सुभद्रा की प्रतिमाओं को आकर्षक ढंग से सुसज्जित रथ पर विराजमान कराया गया। रथ जैसे ही मंदिर परिसर से निकला, श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर भगवान का स्वागत किया। रथयात्रा गांधी नगर तिराहा, छोटा चौराहा, बड़ा चौराहा और आईबीपी चौराहा होते हुए मोतीनगर स्थित हनुमान मंदिर पहुंची। यात्रा मार्ग में जगह-जगह श्रद्धालुओं ने भगवान की आरती उतारी, पुष्प अर्पित किए और महाप्रसाद चढ़ाया। हनुमान मंदिर पहुंचने पर दीप प्रज्ज्वलन के साथ श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए। रथयात्रा में 50 से अधिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक झांकियां शामिल की गईं। रंग-बिरंगी रोशनी से सजे वाहनों पर कलाकारों ने बैंड-बाजों की धुन पर मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग झांकियों को देखने के लिए जुटे रहे। प्रमुख चौराहों पर हुई आकाशीय आतिशबाजी ने आयोजन की भव्यता को और बढ़ा दिया। यात्रा के दौरान भगवान श्रीजगन्नाथ का महाप्रसाद श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। रथ जहां-जहां रुका, वहां आरती करने और प्रसाद चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कुछ स्थानों पर अधिक भीड़ के कारण धक्का-मुक्की की स्थिति भी बनी, जिसे समिति के स्वयंसेवकों और पुलिसकर्मियों ने संभाल लिया। भगवान श्रीजगन्नाथ के रथ का पवित्र रस्सा खींचने के लिए श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ रथ का रस्सा खींचने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी आस्था के चलते महिलाएं, पुरुष, युवा और बुजुर्ग बड़ी संख्या में रथ खींचने पहुंचे। अधिक भीड़ के कारण कुछ स्थानों पर धक्का-मुक्की हुई, जिसमें कुछ श्रद्धालुओं को मामूली चोटें भी आईं।

# उन्नाव पुलिस की बड़ी कार्रवाई,

## 10-10 हजार के दो इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार

उन्नाव पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। अजगैन थाना पुलिस ने शुक्रवार सुबह 11 बजे दो इनामी गैंगस्टर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इन पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की दो मोटरसाइकिलें, तीन मोबाइल फोन और नकदी बरामद की है। दोनों आरोपी गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में वांछित थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में इस कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अजगैन पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त रूप से हिमसिटी के पास से इन आरोपियों को पकड़ा। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान राहुल उर्फ गोलू (26), पुत्र बऊवा, निवासी जालिमखेड़ा मजरा अमरेथा, थाना अजगैन, और गोविंद (20), पुत्र रामस्वरूप, निवासी हिम्मतगढ़, थाना सोहरामऊ के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी थाना अजगैन में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमा संख्या 236/2026 में वांछित थे। गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से एक हीरो सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल मिली, जिस पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी। जांच में पता चला कि यह मोटरसाइकिल थाना दही क्षेत्र से चोरी की गई थी। इसके अतिरिक्त, एक बिना नंबर प्लेट की प्लेटिना मोटरसाइकिल भी बरामद हुई, जो थाना अजगैन क्षेत्र से चोरी हुई थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से तीन चोरी के मोबाइल फोन और 2300 रुपये नकद भी बरामद किए हैं। पूछताछ में पुलिस को दोनों आरोपियों की आपराधिक गतिविधियों की जानकारी मिली। मुख्य आरोपी राहुल उर्फ गोलू के खिलाफ लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट सहित एक दर्जन से अधिक मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं। वहीं, गोविंद के खिलाफ भी चोरी, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर समेत कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी लंबे समय से वाहन चोरी और अन्य आपराधिक घटनाओं में सक्रिय थे। पुलिस ने बरामद वाहनों और मोबाइल फोन के संबंध में आवश्यक साक्ष्य जुटाकर आरोपियों के खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है।

# गंगा के जलस्तर में मामूली गिरावट, तटवर्ती क्षेत्रों में कटान से बढ़ी चिंता

पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा नदी के जलस्तर में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। पिछले दो दिनों में तेजी से बढ़ोतरी के बाद शुक्रवार सुबह जलस्तर में मामूली गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, इस कमी के बावजूद तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की चिंता बनी हुई है, खासकर नवीन गंगा पुल से रेलवे पुल के बीच नदी के किनारों पर तेज कटान के कारण ग्रामीणों और किसानों की परेशानी बढ़ गई है। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के अनुसार, बुधवार शाम छह बजे गंगा का जलस्तर 110.440 मीटर था। गुरुवार सुबह यह बढ़कर 110.560 मीटर पर पहुंच गया और दोपहर दो बजे तक स्थिर रहा। शाम छह बजे इसमें फिर बढ़ोतरी हुई और जलस्तर 110.580 मीटर दर्ज किया गया। शुक्रवार सुबह छह बजे जलस्तर घटकर 110.560 मीटर पर आ गया, जो बीते 12 घंटे में दो सेंटीमीटर की गिरावट दर्शाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश जारी रहने पर गंगा का जलस्तर दोबारा बढ़ सकता है। इसे देखते हुए प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सिंचाई विभाग और संबंधित एजेंसियां जलस्तर की निगरानी कर रही हैं तथा किसी भी संभावित आपदा से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। नवीन गंगा पुल से रेलवे पुल के बीच नदी के तेज बहाव के कारण कटान की रफ्तार बढ़ गई है, जिससे नदी किनारे की भूमि प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि जलस्तर में फिर बढ़ोतरी होती है, तो कटान और तेज हो सकती है, जिससे खेतों और तटीय बस्तियों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। प्रशासन ने गंगा किनारे बसे गांवों के लोगों से सतर्क रहने और नदी के तेज बहाव वाले क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से न जाने की अपील की है। संबंधित विभागों को संवेदनशील स्थानों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन मौसम विभाग द्वारा आगामी दिनों में बारिश की संभावना को देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है।

## मंदिर में पूजा कर रहे दलित समाज के लोगों से अभद्रता का आरोप, जांच शुरू

उन्नाव के हसनगंज थाना क्षेत्र के निंदेमऊ गांव में खाटू श्याम मंदिर में पूजा के दौरान दलित समाज के लोगों के साथ कथित मारपीट और जातिसूचक टिप्पणी का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम विचपरी मजरा निंदेमऊ निवासी अमर पाल पासी ने क्षेत्राधिकारी हसनगंज को दिए शिकायती पत्र में बताया कि गांव के पासी समाज के लोग खाटू श्याम मंदिर में पूजा और आरती कर रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान गांव के राजेश सिंह, उनके पिता श्रीकृष्ण सिंह और परिवार के अन्य सदस्य मंदिर पहुंचे। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उन्होंने पूजा कर रहे लोगों के साथ अभद्रता की, जातिसूचक शब्द कहे और मंदिर में पूजा करने पर जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के अनुसार, विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान लज्जावती, सुनीता, सुरेंद्र कुमार और अमर पाल समेत कई लोग घायल हो गए। पीड़ितों का आरोप है कि घटना के बाद वे हसनगंज थाने पहुंचे, लेकिन तत्काल न तो घायलों का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया और न ही कोई कार्रवाई की गई। इसके बाद क्षेत्राधिकारी हसनगंज को प्रार्थना पत्र देकर एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने और घायलों का मेडिकल कराने की मांग की गई। शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपितों के खिलाफ पहले से भी कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

## नहर किनारे मिले महिला के शव का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार

उन्नाव पुलिस ने बिहार थाना क्षेत्र में नहर किनारे मिले अज्ञात महिला के शव की गुत्थी का खुलासा करते हुए प्रेम संबंधों में विवाद को हत्या की वजह बताया है। एसएसपी ने शुक्रवार को बताया कि घटना के 10 दिन के भीतर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त सेलेरियो कार भी बरामद की है। मामले के खुलासे में करीब 400 सीसीटीवी की फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की मदद ली गई। पुलिस के मुताबिक 6 जुलाई को बिहार-मौरावां मार्ग स्थित केदारखेड़ा नहर पुलिया के पास अज्ञात महिला का शव मिला था। पहचान नहीं होने पर 72 घंटे बाद पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें सिर पर गंभीर चोट लगने से मौत की पुष्टि हुई। इसके बाद हत्या का मुकदमा दर्ज कर स्वाट और सर्विलांस टीम को जांच में लगाया गया। जांच के दौरान 16 जुलाई को लखनऊ के आलमबाग से राधाकांत दुबे उर्फ कक्कू (59), उमेश चंद्र यादव (50) और सुमन वर्मा (40) को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में मुख्य आरोपी राधाकांत ने बताया कि फरवरी में मकान खरीदने के दौरान उसकी मृतका से पहचान हुई थी। दोनों के बीच संबंध बने, लेकिन महिला उसके साथ रहने का दबाव बनाने लगी। इससे परेशान होकर उसने 5 जुलाई को महिला को एक खाली मकान में बुलाया, कोल्ड ड्रिंक में नींद की दवा मिलाकर पिला दी और बेहोश होने पर ईंट से वार कर हत्या कर दी।

## एसडीएम के औचक निरीक्षण में खुली बीआरसी की पोल, मिड-डे मील में मिली खामियां

उन्नाव के बांगरमऊ के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) बृजमोहन शुक्ला ने शुक्रवार को बीआरसी फतेहपुर 84 का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान परिसर में कई अव्यवस्थाएं और मिड-डे मील योजना में खामियां पाई गईं, जिस पर एसडीएम ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। निरीक्षण के समय एसडीएम को बच्चों के लिए भोजन करने वाली थालियां उपलब्ध नहीं मिलीं। जानकारी मिली कि कुछ बच्चे अपने घरों से प्लेट लेकर आते हैं। इस लापरवाही पर एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया। एसडीएम शुक्ला ने व्यवस्था में तत्काल सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ बच्चों तक सही तरीके से पहुंचना चाहिए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान बीआरसी में संचालित होने वाली आईसीटी लैब भी बंद मिली। एसडीएम ने इस संबंध में अधिकारियों से जवाब मांगा और डिजिटल शिक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, पुस्तक वितरण व्यवस्था में भी अनियमितता की शिकायत सामने आई। एसडीएम ने पूरे मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। परिसर में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। बीआरसी के निरीक्षण के बाद एसडीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सफीपुर का भी औचक दौरा किया। यहां भी उन्हें कुछ खामियां मिलीं, जिस पर उन्होंने संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं, साफ-सफाई और दवाओं की उपलब्धता का जायजा लिया।

# आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर सीएम योगी, 1350 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

**मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को बुलंदशहर, अमरोहा और संभल का दौरा करेंगे। इस दौरान वह 1,350 करोड़ रुपये से अधिक की 166 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता सामग्री वितरित कर जनसभाओं को संबोधित करेंगे।**

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तीन जिलों बुलंदशहर, अमरोहा और संभल के दौरे पर रहेंगे। अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे तथा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ वितरित करेंगे। तीनों जिलों में मुख्यमंत्री जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री सबसे पहले बुलंदशहर पहुंचेंगे। यहां वह रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर, खंडवाया में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री नुमाइश मैदान पहुंचेंगे, जहां 574 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 57 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, चाबियां, थर्मल प्रिंटर तथा प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी भी देंगे।बुलंदशहर के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमरोहा के लिए रवाना होंगे। अमरोहा में उनका कार्यक्रम गजरौला स्थित श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया है। यहां मुख्यमंत्री 207 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 43 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, आवास की चाबियां, लैपटॉप और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री यहां भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे और क्षेत्र के विकास कार्यों की प्रगति पर प्रकाश डालेंगे। अमरोहा दौरे के बाद मुख्यमंत्री संभल पहुंचेंगे। संभल में इंटीग्रेटेड मुख्यालय के निकट आयोजित कार्यक्रम में वह शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री 569 करोड़ रुपये की लागत वाली 66 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। विभिन्न योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे तथा सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा भी की जाएगी। मुख्यमंत्री संभल में आयोजित जनसभा को संबोधित कर विकास कार्यों और जACनहितकारी योजनाओं पर सरकार की प्राथमिकताओं को साझा करेंगे। मुख्यमंत्री के इस दौरे को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तीनों जिलों में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और स्थानीय लोगों की मौजूदगी रहने की संभावना है। प्रशासन ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।संभल में कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली होते हुए लखनऊ के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री के इस दौरे के दौरान कुल 1,350 करोड़ रुपये से अधिक की 166 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा, जिससे संबंधित क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के विकास और जनसुविधाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

## नगर निगम की बड़ी योजना, निवेश और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

नगर निगम ने शहर को कारोबार, निवेश और रोजगार का नया केंद्र बनाने के लिए अर्बन चैलेंज फंड (यूसीएफ) के तहत 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक की तीन परियोजनाएं तैयार की हैं। तीनों परियोजनाएं पब्लिग प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर विकसित होंगी। नगर आयुक्त ने बताया कि इनकी लागत का 25 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार अर्बन चैलेंज फंड से, 25 प्रतिशत राज्य सरकार और नगर निगम मिलकर देंगे। बाकी 50 प्रतिशत निजी निवेश और बाजार आधारित वित्तपोषण से जुटाया जाएगा। इससे नगर निगम पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाले बिना बड़े स्तर पर शहरी विकास किया जा सकेगा। न्यू बस अड्डा आरआरटीएस स्टेशन के सामने 43 करोड़ रुपये से बनने वाला मल्टीस्टोरी को-वर्किंग ऑफिस एवं कमर्शल कॉम्प्लेक्स है। इसमें को-वर्किंग स्पेस, कार्यालय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, फूड कोर्ट और पार्किंग सुविधा होगी। परियोजना से रोजगार मिलने के अलावा 1200 करोड़ रुपये से अधिक के निजी निवेश का अनुमान है। क्रॉसिंग रिपब्लिक में निगम की 25 हजार वर्गमीटर जमीन है। यहां 636 करोड़ रुपये से छह एकड़ में इंटीग्रेटेड बिजनेस एंड इनोवेशन हब विकसित होगा। इसमें आधुनिक ऑफिस, को-वर्किंग स्पेस, स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर, रिटेल आउटलेट, फूड कोर्ट, कॉन्फ्रेंस सेंटर, सर्विस अपार्टमेंट और पार्किंग जैसी सुविधाएं होंगी। परियोजना से करीब 15 हजार प्रत्यक्ष और 25 हजार से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अलावा 1200 करोड़ रुपये से अधिक के निजी निवेश का अनुमान है।

## यूपी में 5 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, रामपुर और ललितपुर को मिले नए एसपी

उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत करते हुए शुक्रवार को 5 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। रामपुर के पुलिस अधीक्षक को हटा दिया गया है। इसके अलावा ललितपुर के पुलिस अधीक्षक को लखनऊ मुख्यालय भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक सुरक्षा मुख्यालय लखनऊ से अनिल कुमार सिंह को पुलिस अधीक्षक रामपुर भेजा गया है। अनिल कुमार सिंह 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ से गोपाल कृष्ण चौधरी को सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई है। ललितपुर के पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुस्ताक को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट का पुलिस उपायुक्त बनाया गया है। रामपुर के पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना को आगरा क्षेत्रीय अभिसूचना का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। सेनानायक 43वीं वाहिनी पीएसी एटा से संजीव कुमार बाजपेई को ललितपुर पुलिस अधीक्षक भेजा गया है। बता दें कि इससे पहले बड़ी संख्या में प्रशासनिक फेरबदल किया गया था। 100 से ज्यादा एसडीएम समेत 182 पीपीएस अफसरों के तबादले किए गए थे। इसके अलावा गुरुवार को लखनऊ में निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (SUDA) के रूप में कार्यरत आईएएस अपूर्वा दुबे का केंद्र सरकार में भेज दिया गया है। उनको केंद्र सरकार में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में उप सचिव बनाया गया है।

## निर्धारित समय पर होंगे यूपी विधानसभा चुनाव, चुनाव आयोग के संकेत

यूपी में विधानसभा चुनाव अपने निर्धारित समय पर होने के आसार है। चुनाव आयोग ने इसके संकेत दिए हैं। आयोग का कहना है कि चुनाव संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसका अनुपालन करना होता है। यूपी सहित पांच राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल खत्म हो रहा है। यूपी विधानसभा का कार्यकाल 22 मई तक है, जबकि उत्तराखंड, पंजाब, गोवा सहित अन्य राज्यों का कार्यकाल 28 मार्च के पहले खत्म हो रहा है। इन राज्यों के चुनाव अमूमन फरवरी-मार्च में ही होते हैं। इस बार चुनाव को लेकर संशय इसलिए है क्योंकि यूपी सहित सभी चुनावी राज्यों में 1 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक जनगणना का कार्यक्रम तय है। ऐसे में चुनाव के पहले होने या आगे बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव एक संवैधानिक प्रक्रिया है और जनगणना एक कानूनी प्रक्रिया है। यूपी में विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के पहले चुनाव करवा लिए जाएंगे। दिल्ली में चल रहे चुनाव आयोग के मीडिया सम्मेलन में ऑनलाइन या डिजिटल वोटिंग के कयासों को भी खारिज कर दिया गया। ज्ञानेश कुमार ने शुक्रवार को इंडिया इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी ऐंड इलेक्शन मैनेजमेंट में आयोजित राष्ट्रीय मीडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले एक साल में चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में 786 मुकदमें का सामना किया है। इसमें गोवा उपचुनाव को छोड़कर बाकी सभी मुकदमों में जीत मिली है। यह आयोग के फैसलों की संवैधानिक प्रतिबद्धता को सिद्ध करता है। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि SIR से लेकर चुनाव से जुड़ी सभी प्रक्रिया संविधान और चुनाव से जुड़े कानूनों के तय नियमों के तहत ही आगे बढ़ाई गई है। हाल के विधानसभा चुनावों में रेकॉर्ड मतदान साबित करता हैं कि देश के मतदाताओं का चुनावी व्यवस्था पर गहरा भरोसा है। यूपी में विधायकों के निधन के कारण खाली हुई मऊ की घोसी, सोनभद्र की दुद्धी और बरेली की फरीदपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि विधानसभा का कार्यकाल एक साल से कम बचा है, इसलिए अब चुनाव करवाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। मऊ की घोसी सीट 20 नवंबर 2025 को सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद रिक्त हुई थी। इसके बाद बरेली की फरीदपुर सीट भाजपा विधायक प्रो. श्याम बिहारी लाल के और सोनभद्र की दुद्धी सीट भी सपा विधायक विजय सिंह गेंड के 8 जनवरी को निधन के बाद रिक्त हो गई थी।